रहा है । इसलिए केन्द्र सरकार बिहार में जितने प्रकार के खनिक होते हैं उनकी मूल्य के आधार पर रायल्टी तय करे और 40 प्रतिशत के आधार पर तय करे ।

श्री नरेश यादव (बिहार) : महोदय, श्री जनार्दन यादव जी ने जो खनिज रायल्टी का सवाल उठाया है उससे मैं अपने आपको सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि बिहार खनिज का सब से उत्पादक राज्य है । धरती का दोहन करके देश के अनेक हिस्सों में खनिज जाता है। आज जो खनिज हैं,मिनरल्ज़ हैं उनकी कीमत सौ रुपये से दो सौ रुपये, दो सौ से चार सौ और चार सौ से आठ सौ रुपये हो जाती है, लेकिन रायल्टी वही की वही रहती है । इसलिए जब हमारी धरती का दोहन करके उनकी कीमत दो गुना,चार,दस गुना बढाई जा रही है और कीमत बढाने में कोई सीमा नहीं है तो रायल्टी को भी मूल्यों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए जिससे कि हमारी धरती पर दोहन हो रहा है वह बिहार राज्य को हिस्सा भी मिलना चाहिए ।

इसलिए मैं श्री जनार्दन यादव जी द्वारा उठाए गए सवाल से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए मांग करना चाहता हूं कि 40 प्रतिशत रायल्टी निर्धारित की जानी चाहिए । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री रंजन प्रसाद यादव (बिहार) : मैडम, मैं भी अपने को एसोसिएट करता हूं ।

श्री राम देव भंडारी (बिहार) : महोदया, मैं भी एसोसिएट करता हूं ।

RE: THEIN DAM PROJECT

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA (Punjab): Thank you, Madam. First, I would like to address my Press friends for one reason.

उपसभाध्यक्ष (**श्रीमती कमला सिन्हा**) : आप अपने स्थान से बोलिए ।

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: I would like to correct the Press friends of mine.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): You have to address the Chair, not the Prcsspcrsons. They have been writing my name sometimes as Surinder Singh Singla, sometimes as S. S. Singla. I would like to inform them that my name is Surinder Kumar Singla. Kindly take note of this. Now, I would like to bring one fact to the notice of the Government that a multi-purpose irrigation-cum-power project has been pending for the last thirty years in the State of Punjab. This project is called the Ranjit Sagar Dam or the Thein Dam. When this project was conceived thirty years ago, its cost was only Rs. 90 crores at that time. Rs. 2,600 crores have already been spent on this project and a sum of Rs. 1100 crores has to be given by the Central Government to complete this project. This project was envisaged because the entire water from India is flowing into Pakistan. We have a shortage of water. There is a lot of problem related to the availability of water in the States of Punjab, Haryana and Rajasthan. So, this project was specially designed and conceived to give irrigation facilities to three States—Punjab, Himachal and Jammu and Kashmir. It is not really the cause of concern for the State of Punjab only. It is going to irrigate something like four lakh hectares of land which will produce a million tonne of foodgrains. Shri Chaturanan Mishra is looking for a larger food kitty to be made by the State of Punjab. I would like the Agriculture Minister to take up such projects where there is a great potential of irrigation and power. The former Prime Minister, Shri P. V. Narasimha Rao, had gone to Punjab and offered a lasting solution to the river water disputes among the States of Punjab, Haryana and Rajasthan. He had said that if this project is completed, there will not be any shortage of water; we could distribute water later. He announced there and then that before any final decision on the water dispute is taken among the States of Punjab, Haryana and Rajasthan, this project will be completely funded by the Government of India. Till date, Rs. 67.5 crores have been given. I think this money which is only 50 per cent of the matching money, has to be given by the State of Punjab. Another 50 per cent has to be funded by the Central Government. The State of

Punjab is ready to give its share of funding of 50 per cent. During 1997-98, the total requirement of funds is Rs. 500 crores. Under the accelerated irrgiation benefits scheme, Rs. 1,300 crores are available to the Central Government. This scheme is the best scheme available in the Budget. This entitles a priority funding. My request to the Government is that this is not really going to look after the interests of the State of Punjab, Haryana, Himachal and Rajasthan, and particularly, the poor people of this country, who are looking for cheaper and more food. When we see that the per capita availability of food is declining in the country, we must invest in the irrigation sector where the irrigation potential could be used to produce more foodgrains. Don't waste resource in other areas. This project would be completed in $1^{1/2}$ years. Mr. Agriculture Minister, as you were saying in the morning, if you complete this project, the productivity will increase not only in the State of Punjab but also in the States like Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh. The State of Jammu and Kashmir is a border State. The Agriculture Minister is sitting here. I request him that these funds should be made available to the State of Punjab. I would like to have a response form him. It is going to affect the prospects of the Agriculture Ministry. He has to mobilise the resources. He should provide more funds for this scheme. I would request the hon. Agriculture Minister to respond to my request made about the State of Punjab. Thank you.

कषि मंत्री तथा खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : मैडम, अभी जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है, उसको मैं सिंचाई मंत्री के पास सहानुभूति के साथ भेज दूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा) : धन्यवाद । श्री बलवीर सिंह। आपने एसोसिएट करना था। नहीं है। श्री एस.एस. अहलुवालिया।

RE: DISCONTENTMENT AMONG SIKH MINORITY COMMUNITY OF MAHARASHTRA DUE TO ACQUISITION OF PRIME LAND OF GURDWARA BOARD, NANDED, BY MAHARASHTRA GOVERNMENT

श्री एस.एस.अहलुवालिया (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक विशेष बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। गोदावरी के किनारे बसा शहर नांदेड़ है, जिसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। सिखों के जो पांच शीर्ष धार्मिक स्थान हैं, उनमें से एक है, जहां गुरू गोविन्द सिंह जी ने अपना देह त्यागा था। यह सिखों का एक धार्मिक स्थान है और यहां पांच तख्तों में एक तख्त है। सिखों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज वहां की जमीन, जो अल्पसंख्यक धार्मिक न्यास की जमीन है, उन जमीनों का अधिग्रहण या अर्जन महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, जबरदस्ती किया जा रहा है।

महोदया, ऐसी बात नहीं है गुरुद्वारा बोर्ड के पास जो जमीन है, उसको जनता के हित के लिए या अच्छे कामों के लिए गुरूद्वारे ने स्वयं ही न सौंपी हो। मैं बताना चाहता हूं कि इस्के पहले, महोदया, गुरूद्वारा बोर्ड ने 40 एकड़ जमीन इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने के लिए दी और साथ में 20 लाख रुपया कैश भी दिया कि आप यहां इंजीनियरिंग कॉलेज बना लें। उसके बाद सरकारी अस्पताल बनाने के लिए 8 एकड़ जमीन गुरूद्वारा बोर्ड ने दी कि यहं पर अस्पताल बना लिया जाए। वहां जो बावली साहब हैं, उस बावली साहब के किनारे की 12 एकड़ जमीन, जिसका अपना महत्व है, जहां मेला लगता है, होले महल्ले का मेला या वैसाखी का मेला जो भी हो, वहां लगता है। जितने भी धार्मिक प्रोग्राम होते हैं उनमें वहां लोग इकट्ठे होते हैं, उस 12 एकड़ जमीन को महाराष्ट्र सरकार ने एक्वायर्ड कर लिया है।